REVIVING ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDIA

DR VARINDER BHATIA[1]

ABSTRACT: DECLINE IN ECONOMIC GROWTH RATE IN INDIA IS DISTURBING POLICY MAKERS. GST AND DEMONETISATION IS NOT POSITIVELY RESPONDING TO ECONOMIC PARAMETERS . IT NEEDS A PARADIGM SHIFT IN FOCUS ISSUES OF THE ECONOMY . THIS REASEARCH PAPER EXAMINES IN TO THE PRESENT STATE OF INDIAN ECONOMY AND PUTS AHEAD SOME OPTIONS TO REACH THE POINT OF INFLEXION .

भारतीय अर्थ विवसथा की मौजूदा स्थिति को लेकर भारी चिंता व्यक्त की जा रही है । 2016-17 की पहली तिमाही में जीडीपी 7.9 फीसदी के स्तर पर थी जोकि 2017-18 की पहली तिमाही में जीडीपी तीन साल के सबसे निचले स्तर 5.7 फीसदी पर पहुंच चुकी है।

खासकर पहली तिमाही में जीडीपी में 2.2 फीसदी की गिरावट के बाद विपक्ष ने इसके लिए नोटबंदी के फैसले को जिम्मेदार ठहराया था वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जब आंकड़े आए तो जीडीपी में सीधे2.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई अब सरकार के सामने ये बड़ा सवाल है कि कैसे सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों के साथ आगे बढ़े

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगातार छठी तिमाही में घटी है. आर्थिक समीक्षा-दो में यह अनुमान जताया गया है कि अपस्फीति दबाव के कारण चालू वित्त वर्ष में 7.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना संभव नहीं होगा. इसके साथ ही औद्योगिक वृद्धि दर भी 5 साल में सबसे नीचे आ गया है. निर्यात के समक्ष भी चुनौतियां हैं. अप्रैल-जून तिमाही में चालू खाते का घाटा बढ़कर जीडीपी का 2.4 प्रतिशत या 14.3 अरब डॉलर पहुंच गया रोजगार सृजन के आंकड़े कुछ लाख से आगे नहीं बढ़ पा रहे है

Principal SLBAWA DAV COLLEGE BATALA PUNJAB INDIA

अर्थ विवसथा की स्थिति पर को दो ताजा अध्य यन सामने आए है जो देश की अर्थव्य(वस्थाा की वास्त2विक हालत से परिचित करवाते हैं। एसबीआई रिसर्च ने कहा है कि सितंबर, 2016 से अर्थव्यवस्था में सुस्ती है और यह तकनीकी नहीं बल्कि वास्तविक है। वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन में सामने आया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऋण आवंटन में देरी का शिकार हो गया है।

एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की सुस्ती को दूर करने के लिए सार्वजनिक खर्च बढ़ाने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था सितंबर , 2016 से सुस्ती में है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सुस्ती की वजह तकनीकी रूप से लघु अवधि या क्षणिक भर नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सुस्ती से यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह अस्थायी है या नहीं। हालांकि , रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।

निश्चित रूप से पिछले एक वर्ष में रोजगार , निर्यात और उद्योग-कारोबार में निजी निवेश की भारी कमी ने अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावित किया है. हाल ही में 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' के द्वारा प्रकाशित 'ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2017' में कहा गया है कि रोजगार पैदा करने की सीमित क्षमता का परिदृश्य भारत के लिए गंभीर चुनौती है. यद्यपि सरकार कौशल विकास से रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत दिखी. लेकिन देश में रोजगार नहीं बढ़ने के कई कारण रहे हैं

सर्विस सेक्टर के तहत कई क्षेत्रों में नौकरियों की बढ़ोतरी का अनुपात समान नहीं रहा. कई सेवाओं और आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन के कारण रोजगार घटे हैं. विनिर्माण और कृषि जैसे अधिक रोजगार देने वाले सेक्टर धीमी विकास गति के कारण पर्याप्त रोजगार अवसर निर्मित नहीं कर पाए. जहां पिछले वर्ष विश्व में संरक्षणवाद की बढ़ती लहर ने भारत की नौकरियों को प्रभावित किया. वहीं स्टार्टअप इंडिया , डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को रोजगार बढ़ाने में आशातीत सफलता नहीं मिली. निसंदेह निर्यात क्षेत्र में भी पिछले वर्ष देश के कदम तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए हैं. वैश्विक निर्यात मांग कम होने से वर्ष 2016-17

में निर्यात का मूल्य 274 अरब डॉलर रहा. निर्यात के ये आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं. निर्यात क्षेत्र की चुनौती इसलिए और बढ़ेगी क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के मुताबिक वर्ष 2018 तक भारत को निर्यात को सब्सिडी देना बंद करना होगा

अब विकास के लक्ष्यों के लिए 'नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' यानी नीति आयोग के द्वारा पिछले माह 29 अगस्त को प्रस्तुत किए गए सुधारवादी एजेंडा पर ध्यान दिया जाना होगा. इस एजेंडे में विनिर्माण , छोटे व मझौले उद्योग, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियों की अहम भूमिका की बात कही गई है. सरकार द्वारा मौद्रिक नीति, विनिमय दर नीति, राजकोषीय नीति, निर्यात नीति और रोजगार वृद्धि के लिए उपयुक्त नई राह भी बनाना होगी. ऐसा होने पर ही देश की अर्थव्यवस्था पूरी क्षमता से काम कर पाएगी

REFERENCES

1. India – GDP – real growth rate (%). "Q4 GDP growth at 7.5%; economy grows at 7.3% in FY15". The Economic Times.
2. "AP stands 1st in India in GSDP growth rate". The Times of India. Retrieved 5 April 2017.
3. "Forbes Global 2000 (Ger-Ind)". Retrieved 22 July 2015.
4. "Energy Information Administration (EIA)". Statistical agency of the U.S. Department of Energy. Retrieved 27 October 2007.
5. Centre for Media Studies (2005). "India Corruption Study 2005: To Improve Governance Volume – I: Key Highlights" (PDF). Transparency International India. Archived from the original (PDF) on 26 March 2009.
6. DeLong, J. Bradford (2001). "India Since Independence: An Analytic Growth Narrative" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2 December 2007.